ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, शनिवार 31 जनवरी 2026

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 2 अंक 265

पुलिस महकमे में हो रही आरटीआई की 'तगड़ी रिमांड', 'कस्टोडियल इंटेरोगेशन' में दम तोड़ रहा कानून



रिपोर्ट जयवंत भैरविया

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र का वह कानूनी हथियार है, जो प्रशासनिक फाइलों को जनता की निगरानी में लाने के लिए बनाया गया। कानून सत्ता के गलियारों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करता है। लेकिन उदयपुर पुलिस महकमे में यही कानून अब खुद कस्टोडियल इंटेरोगेशन से गुजरता दिखाई दे रहा है। हर RTI आवेदन को बहानों की रिमांड पर भेज दिया जाता है। उसके बाद उसका जो हाल होता है वह किसी से छिपा नहीं है। जमीनी हकीकत यह हो गई है कि उदयपुर पुलिस ने सूचना के अधिकार के लिए एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग पैटर्न विकसित कर लिया है। इस पैटर्न में न तो समयसीमा का पालन है, न ही अधिनियम की भावना का सम्मान। 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर सूचना देना तो दूर, अधिकांश मामलों में आवेदक को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तय समय बीतने के बाद जो जवाब जारी होते हैं, वे सूचना कम, टरकाने और आवेदक को ही हरैस करने के उपाय ज्यादा लगते हैं।

RTI को घेरने की तैयारशुदा चार्जशीट

पुलिस के बहाने हजार हैं आवेदक के दिल के टुकड़े करने के। कानून बताने, सुप्रीम कोर्ट की नजीरें देने और सूचना आयोग, राज्य पुलिस महकमे के आदेश बताने के बाद भी सूचना नहीं देने का एकदम झक्कास फुलप्रूफ सिस्टम है। आवेदकों को एक जैसी धाराओं का हवाला देते हुए टरकाया जाता है। कहते हैं कि सूचना संधारित नहीं है। सूचना शून्य है। सूचना प्रश्नात्मक है। लोकहित/जनहित स्पष्ट करें। सूचना गोपनीय है। रिकॉर्ड किसी प्रारूप में उपलब्ध नहीं। सूचना स्पेसिफिक नहीं है। धारा 8 के तहत अपवर्जित। घटना से अपना संबंध प्रमाणित करें। याने इतने रेडिमेड बहाने हैं कि पुलिस के पास कि हर प्रश्व आंसू बहाते हुए लाजवाब हो जाता है। कुल मिलाकर, फाइलों में RTI का प्रशासनिक एनकाउंटर होता दिखता है, जहां सूचना जिंदा नहीं बचती।

प्रथम अपील को भूल जाओ, सुनवाई ही नहीं होती

सूचना न मिलने या विधिविरुद्ध उत्तर के बाद जब आवेदक प्रथम अपील का सहारा लेता है, तो मामला और गंभीर हो जाता है। उदयपुर पुलिस में प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदस्थ पुलिस अधीक्षक एवं नामित अधिकारी एसपी साहब के समक्ष अपीलें प्रायः लंबित फाइल बनकर रह जाती हैं। न सुनवाई, न आदेश—यानी अपीलीय प्रक्रिया भी डेड एंड पर आकर रूक जाती है।

सूचना आयोग के आदेश भी बेअसर

स्थिति यहीं नहीं रुकती। राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित स्पष्ट आदेशों और स्थापित न्यायिक दृष्टांतों के बावजूद, उदयपुर पुलिस कई मामलों में सूचना देने से इनकार कर आयोगीय आदेशों की अवहेलना करती नजर आती है। यह रवैया सीधे तौर पर संवैधानिक संस्था की अवमानना की श्रेणी में आता है।

धारा 4 भी फाइलों में बंद

RTI अधिनियम की धारा 4—जो स्वप्रकाशन और पारदर्शिता की रीढ़ मानी जाती है—उदयपुर पुलिस के रिकॉर्ड में शायद ही दिखाई देती है। लोक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से बचने का यह रवैया इस आशंका को और मजबूत करता है कि सूचना के उजागर होते ही कई प्रशासनिक गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं।

CCTV फुटेज केवल दिखावे के, जनता का पैसा मगर पहरा पुलिस का

थानों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट, राज्य सूचना आयोग और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्पष्ट दिशा-निर्देश मौजूद हैं। इसके बावजूद उदयपुर पुलिस फुटेज उपलब्ध कराने से बचने के लिए नए-नए तकनीकी और प्रक्रियात्मक हथकंडे ईजाद कर रही है। अब गोपनीयता का तर्क कम, और आवेदक से लोकहित, जनहित और घटना से संबंध पर निबंध लिखवाने की शर्त ज्यादा देखने को मिल रही है—ताकि अधिकार को प्रक्रिया के जाल में उलझाकर निष्प्रभावी किया जा सके। ठान रखा है कि सूचना नहीं देनी है तो नहीं देनी है। इसके लिए चाहे जितने कानून बताए जाएं। सूचना थाने की दहलीज तक नहीं लांघ पाती है बेचारी।

पूरा परिदृश्य कई असहज सवाल खड़े करता है

क्या सूचना का अधिकार अधिनियम का सम्मान कराने के लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा?

क्या सरकार और जनप्रतिनिधियों की इस प्रशासनिक उदासीनता पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और सबसे बड़ा सवाल—उदयपुर पुलिस RTI की आत्मा को कब तक हिरासत में रखेगी?

क्रैश हुई चांदी, 1.10 लाख गिरकर 2.91 लाख पर आईः सोना 20 हजार रुपए सस्ता, 1.49 लाख रुपए पर आया; वजह मुनाफा वसूली



24 न्यूज अपडेट

गोल्ड और सिल्वर मार्केट 30 जनवरी को क्रैश हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 1.10 लाख रुपए (27%) गिर गई।

अब 1 किलो चांदी 2.91 लाख रुपए में मिल रही है। एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को चांदी 4.01 लाख रुपए प्रति किलो में मिल रही थी।

MCX पर सोने में भी 20 हजार रुपए (12%) की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1.49 लाख रुपए पर आ गया। 29 जनवरी को सोना 1.69 लाख रुपए पर था।

सोने-चांदी में गिरावट की 2 वजह

प्रॉफिट बुकिंगः सोने-चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया।

फिजिकल डिमांड में कमीः ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ीं।

सर्राफा बाजार में चांदी 40 हजार रुपए सस्ती

सर्राफा बाजार में चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, एक किलो चांदी 3,39,350 रुपए किलो पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,795 रुपए पर आ गया है।

ये बाजार शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, इस वजह से यहां कीमतों में वायदा बाजार की तुलना में कम गिरावट देखी गई। वायदा बाजार रात 12 बजे तक चलता है। यहां शेयर बाजार की तरह हर सेकेंड बोलियां लगती हैं जिससे दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं।

बिना सीमांकन के तैयार हो रही आयड़ की सवा करोड़ की फेंसिंग, अतिक्रमणकारियों की बल्ले—बल्ले!!!



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। नगर निगम द्वारा आयड नदी के दोनों किनारों पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से कराई जा रही चैनलिंक फेंसिंग अब पर्यावरण संरक्षण से ज्यादा अतिक्रमण को स्थायी रूप देने की कवायद के रूप में देखी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि नदी का बिना वैधानिक सीमांकन किए बिना ही फेंसिंग कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र पर पहले से मौजूद कब्जों को सरकारी मुहर मिलने का खतरा पैदा हो गया है। शनिवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना द्वारा एआरसी (एनुअल रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट) के तहत कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस निरीक्षण में आयड नदी में चैनलिंक फेंसिंग और नाला टेपिंग कार्य भी शामिल रहा। आपको बता दें कि नदी के मूल प्रवाह क्षेत्र और उसकी वास्तविक चौड़ाई को लेकर अब तक कई दावे विधायक से लेकर अधिकारियों तक ने किए मगर जमीन पर अब तक कोई स्पष्ट सीमांकन सामने नहीं आया है। कोई रजवाडों का नक्शा बताता है तो कोई आजादी के बाद लगे मोटाम की याद दिलाता है जबकि यही किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले की अनिवार्य शर्त है।

सीमांकन बिना फेंसिंग = कब्जे की हदबंदी

शहर के पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक आयड नदी की राजस्व और भौगोलिक सीमा तय नहीं होती, तब तक की गई कोई भी फेंसिंग वास्तव में नदी को नहीं, बल्कि अतिक्रमणकारियों की जमीन को सुरक्षित कर रही है। फेंसिंग के खंभे जहां-जहां गड़े हैं, वहीं भविष्य में यही नदी की सीमा है का तर्क खड़ा किया जा सकेगा—यानी आज की चूक कल का स्थायी दस्तावेज़। याने कल लोग कहेंगे कि सरकारी फेंसिंग है, यही तो सीमांकन है। हमने थोडे ना सीमांकन करवाया।

नाला टेपिंग बनाम प्राकृतिक नदी

निरीक्षण के दौरान आयड नदी में सीवर नाला टेपिंग कार्य का भी जायजा लिया गया। उद्देश्य बताया गया कि दूषित पानी को नदी में जाने से रोका जाए, लेकिन सवाल यह है कि जब नदी को प्राकृतिक स्वरूप में रहने ही नहीं दिया जा रहा। इतना पानी आने व नदी के ऐसी की तैसी होने के बाद भी उसमें भराव डलवाया गया, लाल मिटटी डलवाई गई। लोग पूछ रहे हैं कि ये किस आधारपर हो रहा है जबकि अगली बारिश में फिर सब बह जाना है। ये किस इंजीनियर की खोपड़ी की उपज है, मगर इस पर अधिकारियों की नजर ही नहीं जा रही है।

इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए टूटेंगे रेम्प

निरीक्षण में न्यू भूपालपुरा क्षेत्र में 80 लाख रुपए की लागत से हो रहे इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य को लेकर भी गंभीर तकनीकी सवाल सामने आए हैं। आपको बता दें कि टाइल्स के नीचे की जमीन को कच्चा और जल-संचरण योग्य छोड़ने के बजाय सीमेंट का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। इससे बरसात का पानी जमीन में उतरने के बजाय सतह पर बह रहा है, जो भविष्य में जलभराव और शहरी बाढ़ की वजह बन सकता है। उल्लेखनीय है कि इस तकनीकी पहलू की स्वतंत्र जांच या हाइड्रोलॉजिकल मूल्यांकन की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया गया कि जिनके रेम्प बीच में आ रहे हैं उनको तोड़ कर टाइल्स लगाएंगे।

फेंसिंग तोड़ने पर मुकदमा करेंगे, नीति पर सवाल बरकरार

निरीक्षण के दौरान गट्टानी फार्म हाउस के पास फेंसिंग तोड़े जाने की शिकायत पर आयुक्त ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज करने के निर्देश दिए। कार्रवाई अपनी जगह उचित है, लेकिन बुनियादी सवाल जस का तस है—क्या यह फेंसिंग वास्तव में नदी की है या नदी के भीतर हो चुके कब्जों की? नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण के अंत में सभी कार्यों को तकनीकी मानकों के अनुरूप और उच्च गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। लेकिन शहर पूछ रहा है कि तकनीकी मानकों में क्या नदी का सीमांकन और प्राकृतिक प्रवाह भी शामिल है या नहीं? नदी की जो हत्या हो रही है उसको कौन बचाएगा??

इस साल आईफोन 18 की लॉन्चिंग टल सकती हैः सिर्फ फोल्डेबल और प्रो मॉडल्स लाएगी एपल, वजह- महंगी चिप



24 न्यूज अपडेट

टेक कंपनी एपल आमतौर पर हर साल सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज के चार मॉडल लॉन्च करती है, लेकिन इस बार कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

जापान की मीडिया कंपनी निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, एपल साल 2026 के अपने एनुअल इवेंट में आईफोन 18 का बेस मॉडल लॉन्च नहीं करेगा। कंपनी इसे साल 2027 की पहली छमाही तक के लिए टाल सकती है।

चिप की बढ़ती कीमतें और मुनाफा बढ़ाना है वजह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल ने यह फैसला मैमोरी चिप और अन्य मटेरियल्स की बढ़ती कीमतों के कारण लिया है। कंपनी अपने संसाधनों को ऑप्टिमाइज करना चाहती है ताकि, प्रीमियम मॉडल्स से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया जा सके।

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन और एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने भी संकेत दिए हैं कि एपल इस साल आईफोन 18 को रिलीज करने के मूड में नहीं है। इसके बजाय, कंपनी आईफोन 18E मॉडल के साथ इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

सुनीता मीणा लगातार दूसरे वर्ष भारतीय लेक्रोज टीम की कप्तान घोषित



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 31 जनवरी। रियाद सऊदी, अरब में 1 से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाली एशियाई लैक्रोज गेम्स में उदयपुर की बेटी सुनीता मीणा को लेक्रोज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इसकी जानकारी सीईओ तौफीक लारी ने दी। सुनीता को कप्तान बनाए जाने पर उदयपुर जनजाति क्षेत्र में हर्ष की लहर है । सुनीता को कप्तान बनने पर उदयपुर लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राजस्थान लेक्रोज संघ के अध्यक्ष अशोक परनामी, उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, आयुक्त क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग कन्हैयालाल स्वामी, उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता, आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण राहुल जैन, जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल सहित लैक्रोज के खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। साथ ही प्रतियोगिता में सफलता की शुभकामनाएं दीं। सुनीता मीणा की कप्तानी में ही पिछले वर्ष भारतीय टीम ने समरकंद उज्बेकिस्तान में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था।



संपादकीय : गरीबी का पैमाना

देश में सबसे निचले तबके की पांच से दस फीसद आबादी के उपभोग व्यय में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यानी इस वर्ग के लोग अपनी जरूरत के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि गरीबों की माली हालत में सुधार हुआ है। संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रपट में गरीबी का दायरा कम होने की यह तस्वीर उकेरी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार के सबसिडी, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता जैसे कदमों के परिणामस्वरूप कमजोर वर्ग अभाव से उबरे हैं। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तस्वीर बदली है। मगर सवाल है कि गरीबी से उबरने का आकलन करने के पैमाने क्या हैं? क्या इस प्रक्रिया में सिर्फ वस्तुओं की खरीद पर खर्च बढ़ने को आधार बनाना काफी है? समीक्षा में आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि देश में उपभोग असमानता में कमी आई है, मगर क्या वास्तव में इसे गरीबी कम होने का सूचक माना जा सकता है ? आर्थिक समीक्षा रपट के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच समाज के सबसे निचले वर्ग के प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय में वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी गई है तर्क दिया गया है कि सरकारी नीतियों का आय वितरण पर महत्त्वपूर्ण असर हुआ है, जिससे गरीब तबके की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। मगर इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि जिसे 'व्यय की क्षमता' बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है, उसका आधार क्या है। इसमें दोराय नहीं कि सामान्य तौर पर किसी भी परिवार के खर्च करने की क्षमता में तभी इजाफा होता है, जब उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। इसके बिना अगर गरीब परिवारों का वस्तुओं की खरीद पर व्यय बढ़ रहा है, तो वह महंगाई और मजबूरी से उपजी परिस्थितियों का नतीजा भी हो सकता है। जाहिर है, जैसे- जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर हर किसी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आमदनी बेहद कम होने और किसी वस्तु की अत्यधिक जरूरत पड़ने पर गरीब परिवार बैंक या साहूकार से कर्ज लेकर भी खर्च करते हैं। इस सूरत में ऐसे परिवारों के व्यय में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, पर क्या इसे यह मान लिया जाए कि वे गरीबी से उबर गए हैं! यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर सबसिडी या मुफ्त राशन देने से गरीबी कम हो जाती है। और अगर देश में जमीनी स्तर पर वास्तव में गरीबी कम हो गई है, तो आज भी सरकार की ओर से करीब अस्सी करोड़ लोगों को तय मात्रा में मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। कोविड काल में शुरू की गई इस योजना को एक जनवरी, 2024 से अगले पांच साल तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में जरूरी है कि गरीबी को आंकड़ों के जरिए कागजों पर खत्म करने की बजाय इस दिशा में धरातल पर प्रयास किए जाएं। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उनकी आजीविका के स्थायी साधन विकसित करना जरूरी है और यह तभी संभव हो पाएगा, जब गरीबों के लिए शिक्षा और रोजगार के सरते, सुलभ और पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि बजट में सरकार इस मसले पर कोई ठोस घोषणा करेगी।

ताक पर गरिमा

यह विडंबना ही है कि भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआइ) ने एक ऐसे व्यक्ति को अहम जिम्मेदारी सौंप कर टीम के साथ जार्डन भेज दिया, जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का आरोपी है। गौरतलब है कि 'इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन' (आइटीपीएफ) विश्वकप क्वालीफायर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जो भारतीय दल जार्डन गया है, उसमें बलात्कार के आरोपी कर्नल (सेवानिवृत्त) तरसेम सिंह वरैच को प्रबंधक और कोच के रूप में भेजा गया है। स्वाभाविक ही इसे लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया है कि ऐसे अपराध के आरोपी को इस हैसियत कैसे भेजा गया। सवाल है कि वहां भेजने के फैसले से पहले क्या ईएफआइ ने एक बार यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि इसका खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि किस स्तर पर प्रभावित होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता में भेजे जाने वाले दल में किसी व्यक्ति को शामिल करने से पहले क्या उसके बारे में कोई पड़ताल नहीं की जाती ? अगर ईएफआइ को तरसेम सिंह वरैच पर लगे आरोपों और कानूनी मामले के बारे में जानकारी थी, तो उसे भारतीय दल के साथ भेजने का क्या आधार था ? मामले की गंभीरता को देखते हुए ही आइटीपीएफ ने ईएफआइ से तुरंत उचित कार्रवाई करने और साथ ही प्रतियोगियों की सुरक्षा तथा खेल की गरिमा कायम रखने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। हैरानी की बात यह है कि अपराध की गंभीरता और तथ्यों के मद्देनजर ही जो आरोपी व्यक्ति जमानत पर बाहर है, उसे खेल अधिकारियों ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति भी दे दी। जबकि इससे पहले भी तरसेम को झूठी पहचान बनाकर फायदा उठाने से संबंधित एक अन्य मामले में महासंघ ने 2022-24 तक के लिए निलंबित कर दिया था। क्या इस तरह के फैसले को खेल की गरिमा और देश की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए ? जहां किसी भी खेल में खिलाड़ियों से लेकर कोच या प्रबंधक आदि के दल में चुने जाने के लिए उसकी स्वच्छ छवि को एक शर्त के तौर पर देखा जाना चाहिए, वहां इस पहलू की अनदेखी करने को किस तरह देखा जाएगा!

ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट 2026 का भव्य समापन, खेल प्रेमियों का उमड़ा हुजूम



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। 1ST ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट 2026 का शनिवार को सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित भव्य समारोह के साथ गरिमामय समापन हुआ। समापन समारोह में देशभर से आए खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान खेल प्रेमियों का भारी उत्साह देखने को मिला और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह के मुख्य अतिथि उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, गुजरात सरकार के फायर सर्विस डायरेक्टर नलिन चौधरी , भारत सरकार के डिप्टी फायर एडवाइजर मोरेश्वर कुड़किलवर आदि रहे। इस अवसर पर उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

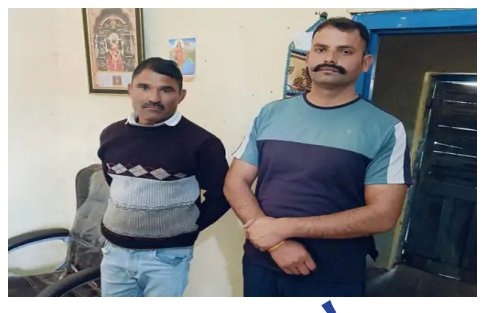
खेल ही भारत की भाषा - आयुक्त।

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने अपने संबोधन में आयोजन की सफलता के लिए आयोजन समिति के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी सहित अभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करना गौरव की बात है। आयुक्त खन्ना ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त माध्यम हैं। भारतवर्ष की पहचान हमारी खेल संस्कृति से होती है। उन्होंने कहा कि उदयपुर आए कई खिलाड़ियों को संभवतः यहां की स्थानीय भाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन खेल की भाषा सबको समझ में आती है। खेल के माध्यम से सभी खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को समझा और आपसी भाईचारे व एकता का संदेश दिया। यही भारत की असली ताकत है, जो विविधता में एकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक समन्वय को भी मजबूत किया। इस तरह के आयोजन देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुक्त ने कहा कि उदयपुर शहर को इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिला, जो शहर के लिए गर्व का विषय है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि समारोह के दौरान विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा गया। खिलाड़ियों ने भी आयोजन की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उदयपुर में उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं और आतिथ्य मिला। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। राजस्थानी संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियों ने समारोह को और अधिक आकर्षक बना दिया। बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन समारोह में उपस्थित रहे, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी नवदीप सिंह बग्गा, शिवराम मीणा ने विभिन्न राज्यों से आए अग्निशमन अधिकारीयो का नगर निगम की तरफ से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया।

प्रतियोगिता का रंगारंग समापन।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि शनिवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चौधरी ने कहा कि यहां आए खिलाड़ियों के साथ-साथ शहरवासियों के लिए भी यह आयोजन लंबे समय तक यादगार रहेगा। इस सफल आयोजन ने यह साबित किया कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का सशक्त माध्यम भी हैं जो हमने सफलता पूर्वक अर्जित किया है। चौधरी ने जिला खेल अधिकारी पालीवाल का हार्दिक आभार व्यक्त कर सहयोग हेतु धन्यवाद प्रेषित किया।

वर्दी की जेब में घूस, थाने की मेज़ पर सौदेबाज़ी, एसीबी के जाल में हेड कॉन्स्टेबल–सिपाही, 2 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

बांसवाड़ा। कानून की रखवाली करने वाली वर्दी जब खुद कानून को ताक पर रख दे, तो भरोसे की नींव हिलना तय है। बांसवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पाटन थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए छोटी सरवा पुलिस चौकी के हेड कॉन्स्टेबल सुरेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल जयपाल सिंह को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला वाहन सुपुर्दगी और नुकसान भरपाई की फाइल को आगे बढ़ाने के बदले अवैध वसूली का है।

फाइल आगे बढ़ाने की कीमत तय

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना के अनुसार, परिवादी के परिचित का कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें परिवादी की निजी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रकरण पाटन थाने में दर्ज हुआ और जांच हेड कॉन्स्टेबल सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई। आरोप है कि सुरेंद्र सिंह ने वाहन सुपुर्दगी की फाइल तैयार करने और नुकसान की उचित राशि दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग की और लेन-देन के लिए अपने मुंशी कॉन्स्टेबल जयपाल सिंह को आगे कर दिया। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने पहले सत्यापन कराया, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों की भूमिका स्पष्ट हो गई। इसके बाद शनिवार को जाल बिछाया गया। तय योजना के अनुसार, कॉन्स्टेबल जयपाल सिंह ने जैसे ही 2 हजार रुपए की रिश्वत ली, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। मौके पर मौजूद हेड कॉन्स्टेबल सुरेंद्र सिंह को भी षड्यंत्र में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई एसीबी महानिरीक्षक राजेश सिंह और उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के साथ-साथ उनके आवासों की तलाशी भी ली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह वसूली किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा तो नहीं।

यशवंत आंचलिया पुनः सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 31 जनवरी। श्री सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर के त्रि-वार्षिक चुनाव 2026-29 में अध्यक्ष पद पर यशवंत आंचलिया पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी राजकुमार फत्तावत ने बताया कि अध्यक्ष पद हेतु एसोसिएशन के विधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न की गई एवं विभिन्न चरणों के पश्चात इस पद हेतु एक ही नामांकन पत्र प्राप्त होने पर चुनाव अधिकारी राजकुमार फत्तावत द्वारा अध्यक्ष पद पर यशवंत आंचलिया को निर्वाचित कर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नरेन्द्र सिंघवी, प्रकाश सिंघवी, महेन्द्र सोजतिया, कमलेश हाथी, महावीर सिंघटवाडिया, मयंक लोढ़ा, कैलाश सोनी सहित श्री सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर के सैकड़ों सदस्य एवं व्यापारीगण उपस्थित थे।

खेल की उम्र, ज़हर का स्वादः बांसवाड़ा में चार मासूमों की जान पर बन आई



24 न्यूज अपडेट

बासवाड़ा। शाम ढलते-ढलते नल्दा गांव की एक गली में खेल बच्चों का था, लेकिन खतरा ऐसा निकला जिसने पूरे गांव की सांसें थाम दीं। आंबापुरा थाना क्षेत्र में चार मासूम बच्चों ने खेल-खेल में रतनजोत के जहरीले बीज खा लिए, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टियां, चक्कर और घबराहट—लक्षण ऐसे थे कि परिजन पल भर में समझ गए, मामला साधारण नहीं है। बताया जा रहा है कि रक्षीता, हर्षिता और धनराज (तीनों संदीप की संतान) तथा रितिका (देवीलाल की पुत्री) घर के बाहर खेल रही थीं। पास ही उगे रतनजोत के पौधे से तोड़े गए बीज मासूम जिज्ञासा में मुंह तक पहुंचे—और वहीं से खतरे की शुरुआत हो गई। कुछ ही समय में बच्चों को मिचली आने लगी, उल्टियां हुईं और तेज चक्कर महसूस होने लगे। स्थिति की गंभीरता भांपते ही परिजन देर किए बिना बच्चों को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने बिना औपचारिकताओं में उलझे उपचार शुरू किया। समय पर मिली चिकित्सा ने राहत दी—चारों बच्चों की हालत फिलहाल नियंत्रण में और खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेडिकल टीम की निगरानी लगातार जारी है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं ग्रामीण इलाकों में बार-बार सामने आती हैं, जहां घरों और खेतों के आसपास रतनजोत जैसे जहरीले पौधे आमतौर पर उगे रहते हैं। छोटे बच्चे इन्हें पहचान नहीं पाते और खेल के दौरान अनजाने में बीज खा लेते हैं, जो शरीर पर गंभीर असर डालते हैं।

अवैध क्वार्ट्ज खनन पकड़ा, जेसीबी व ट्रैक्टर चालक मौके से फरार, पटवारी की सतर्कता से रुका काम

24 न्यूज अपडेट

सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। नगर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत जेठाना के पटवार मंडल जेठाना अंतर्गत चारागाह भूमि खसरा संख्या 579 में अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थरों का खनन किया जा रहा था। पटवारी की सतर्कता से कार्य रुकवाया गया। जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से पत्थर भरकर ले जाए जा रहे थे, लेकिन कार्रवाई से पहले ही जेसीबी व ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। अवैध खनन की जानकारी मिलने पर पटवारी जेठाना पूनम सेवक ने मौके पर पहुंचकर कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए खनन कार्य तत्काल रुकवाया। पटवारी द्वारा बीट प्रभारी अजय सिंह एवं ग्राम सरपंच को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया तथा स्थिति की मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार सागवाड़ा को सौंपी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार सागवाड़ा डॉ. आर. सी. वडेरा ने संबंधित थाना प्रभारी व खनन विभाग को पत्र लिखकर अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह संपन्न : 50 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का हुआ सम्मान।



24 न्यूज अपडेट

खेरवाड़ा, महावीर इंटरनेशनल केंद्र खेरवाड़ा एवं तारा सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निचला खेरवाड़ा स्थित तहसील परिसर में स्थापित पेंशनर समाज भवन के सभागार में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता पेंशनर समाज अध्यक्ष जीवत राम ननोमा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि एमआई केंद्र के संरक्षक दिनेश जैन रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पेंशनर समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरलीधर मेहता, एमआई अध्यक्ष मुकेश कलाल एवं एमआई सचिव जितेंद्र जैन मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तारा सेवा संस्थान की आरती ने बताया कि समारोह में 50 से अधिक 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर, आम नागरिक एवं महिलाओं को पगड़ी पहनाकर, उपर्णा ओढ़ाकर सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया साथ ही संस्था की ओर से महावीर इंटरनेशनल केंद्र खेरवाड़ा को अभिनंदन पत्र प्रदान कर इस सराहनीय कार्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने सम्मानित किया गया। समारोह को मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, पेंशन समाज संरक्षक शांतिलाल व्यास, वरिष्ठ सदस्य कन्हैया लाल जैन एवं शंकर लाल पंचाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरलीधर मेहता एवं तारा संस्था की कार्यक्रम समन्वयक आरती चित्तौडा ने संबोधित किया। सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों को संस्थान द्वारा किए गए कार्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। समारोह में एमआई के उपाध्यक्ष पुष्कर पंचोली, संयुक्त सचिव दिलीप जैन, कोषाध्यक्ष अल्पेश जैन,पूर्व अध्यक्ष हेमचंद लबाना, निर्मल गांधी एवं बसंत कोठारी, अर्जुन पंचाल, मुकेश जैन पेंशनर समाज के संरक्षक शांति लाल व्यास,वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरलीधर मेहता, कोषाध्यक्ष शांति लाल पंचोली सहित एमआई, पेंशनर समाज एवं तारा सेवा संस्थान के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार आरती चित्तौडा द्वारा व्यक्त किया गया।

अबकी बार, मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर तैयार, जनता के पैसों से आया नेताओं का अमृतकाल

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान में सुशासन अब चार पहियों पर सवार हो चुका है—और वो भी टोयोटा फॉर्च्यूनर पर सरपट भाग रहा है। भजनलाल सरकार के दौर में यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो गई और जनता के पैसों का धुआं करते हुए पहली बार मंत्रियों को सरकारी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ आवंटित की जा रही हैं, ताकि जनसेवा की राह में कहीं उनकी पीठ न दुख जाए। पंथ् है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पांवों में छाला न पड़ जाएं.... के दिन अब चले गए। अब तो पेट का पानी भी ना हिले और एसी का तापमान भी लोकतांत्रिक स्तर से नीचे न जाए ऐसी व्यवस्था हो रखी है। आखिर जनता का पैसा है ही सदुपयोग के लिए तो उसका दिल खोल कर इस्तेमाल हो रहा है। सत्ता को सुकून मिलेगा तभी तो विकास का अमृत काल दिखाई देगा। सरकार ने हाल ही में दो दर्जन से अधिक नई फॉर्च्यूनर के ताज़ा मॉडल खरीदे हैं, एकदम चमामच। अब ये गाड़ियाँ मंत्रियों को एक-एक कर आवंटित की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आज भी कई मंत्रियों को नई गाड़ियों की चाबी सौंप दी गई। यह वही राजस्थान है, जहाँ कभी सरकारी जीप में मंत्री बैठते थे और जनता समझती थी कि नेताजी भी हमारे जैसा है। अब फॉर्च्यूनर में बैठा मंत्री दूर से ही बता देता है कि हम आपके जैसे नहीं हैं, बल्कि यह कह देगा कि हम आपके हैं कौन?? विडंबना यह है कि कई मंत्रियों के पास पहले से निजी फॉर्च्यूनर मौजूद हैं।



लेकिन लोकतंत्र में निजी और सरकारी सुख-सुविधा का संतुलन भी तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। घर की फॉर्च्यूनर थक जाए तो दफ़्तर की फॉर्च्यूनर तैयार खड़ी मिले। इसे ही कहते हैं सरकारी नीतियों को बेहतरीन इंस्तेमाल। यह अब तक की सबसे महंगी लेकिन सबसे ज़रूरी व्यवस्था बताई जा रही है। क्योंकि मंत्री अगर आराम से नहीं पहुँचेंगे तो जनता तक काम कैसे पहुँचेगा? अब सवाल यह नहीं कि 13–14 करोड़ रुपये खर्च हुए या नहीं, सवाल यह है कि यह खर्च किस दर्द की दवा है। या फिर दर्द का ही कारण तो नहीं है?? क्या सड़क पर गड्ढे में फिसल कर कुचलते हुए बच्चे नहीं दिखाई देते? क्या स्कूलों की जर्जर हालत और अस्पतालों की व्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती हैं। मगर अब फॉर्च्यूनर आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। आप अगर खबर पढ़ रहे हैं तो आपको भी मुबारक। सुपर-लग्ज़री फॉर्च्यूनर कि किश्तें आपको ही देनी हैं। आप देख कर खुश होकर किश्त देना चाहते हैं या फिर मंत्रियों के अमृत काल को कोस कर ये तो आपको ही तय करना है। असल चिंता यह नहीं कि मंत्री आराम से सफ़र कर रहे हैं। चिंता यह है कि अब ये सरकारी नीति बन चुकी है कि ये आराम का मामला है, अपुन की चॉइस का मामला है। सादगी के जुमले को सिर्फ भाषणों में बंधक बना कर रख दिया गया है। गांधी जी कहते थे—सत्ता में बैठे व्यक्ति को जनता के जीवन-स्तर के करीब रहना चाहिए। राजस्थान में प्रयोग उल्टा हो रहा है—सत्ता को ऊपर उठाया जा रहा है, जनता को समझाया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर को देख कर सपने देखो, एक दिन उसे पाने की तमन्ना भी पूरी होकर रहेगी।

80 साल पुराने मृत व्यक्ति के नाम पर जैन समाज की ज़मीन की हो गई रजिस्ट्री



24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ा। राजस्व रिकॉर्ड की फाइलों से निकलकर एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें 80 वर्ष पहले दिवंगत हो चुके यति के नाम पर न केवल दस्तावेज़ जिंदा कर दिए गए, बल्कि सुवाणा श्वेतांबर जैन समाज ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री भी कर दी गई। मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी आधार, पैन कार्ड, फोटो, उम्र और पता तक गढ़कर 80 लाख रुपये का सौदा रच दिया गया—और सिस्टम सब देखता रहा। मामले का पर्दाफाश किसी जांच एजेंसी ने नहीं, बल्कि संयोग ने किया। ट्रस्ट की जमीन से सटी अपनी खरीदी हुई भूमि का डिमार्केशन करवाते समय एक व्यक्ति को कागज़ों में सटी हुई जमीन किसी और के नाम दर्ज दिखी। यह नाम था—आसींद निवासी मोहम्मद मुन्ना। यहीं से शक की सुई ट्रस्ट भूमि की ओर घूमी और पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल, सुवाणा कस्बे में स्थित करीब दो बीघा भूमि वर्षों से सुवाणा श्वेतांबर जैन समाज ट्रस्ट के नाम दर्ज थी। यह भूमि उपासरा के यति श्री केसरी चंद तथा शांतिनाथ जैन मंदिर से संबद्ध थी। ट्रस्ट पदाधिकारी प्रकाश चपलोत को जब यह जानकारी मिली, तो दस्तावेज़ खंगाले गए। नतीजा हैरान करने वाला था—17 अक्टूबर 2025 को यह जमीन मोहम्मद मुन्ना के नाम रजिस्टर्ड पाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिन यति श्री केसरी चंद के नाम पर यह सौदा दिखाया गया, उनकी मृत्यु लगभग 80 वर्ष पहले हो चुकी है। इसके बावजूद उनके नाम से फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए गए, उम्र घटा-बढ़ाकर दर्ज की गई और फोटो तक जालसाजी से जोड़ी गई। सेल डीड में केसर चंद का उल्लेख भी तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया। रजिस्ट्री दस्तावेज़ों में मोहम्मद मुन्ना (पिता अब्दुल मजीद) को खरीददार बताया गया है, जबकि रामकरण जाट और मोहम्मद मंसूरी को गवाह बनाया गया। सवाल यह नहीं कि फर्जीवाड़ा हुआ—सवाल यह है कि ट्रस्ट की ऐसी जमीन, जिसे न बेचा जा सकता है और न खरीदा, वह बिना ठोस जांच के रजिस्ट्री की मेज़ तक कैसे पहुंच गई? मामला सामने आने के बाद शनिवार को जैन समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर व एसपी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ट्रस्ट अध्यक्ष नेमकुमार संघवी ने स्पष्ट कहा कि रेवेन्यू विभाग की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए—क्योंकि बिना मिलीभगत या घोर लापरवाही के यह खेल संभव नहीं। समाज की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सभी संबंधित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि इस पूरे प्रकरण में शामिल हर व्यक्ति—चाहे वह दलाल हो, गवाह हो या जिम्मेदार अधिकारी—के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।

कबाड़ से खजाना: जयपुर डिस्कॉम ने 104 करोड़ 39 लाख के भंगार की नीलामी से रचा नया इतिहास



24 न्यूज अपडेट

जयपुर। जिस अनुपयोगी सामग्री को कभी विभागीय उदासीनता और फाइलों की धूल में दबा मान लिया गया था, वही जयपुर डिस्कॉम के लिए इस वर्ष आर्थिक संबल बनकर उभरी है। निगम ने स्क्रैप मैटेरियल की सुनियोजित नीलामी से अब तक 104 करोड़ 39 लाख रुपये का राजस्व अर्जित कर न केवल अपने ही पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए, बल्कि सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन का उदाहरण भी पेश किया है। डिस्कॉम के 13 वृत्त भंडारों में वर्षों से पड़े पुराने ट्रांसफॉर्मर, मीटर, केबल, वीसीबी, खराब ऑयल, लकड़ी के बॉक्स, लोहे के ड्रम और नाकारा वाहन—जो कभी नुकसान का कारण माने जाते थे—अब नियमित ऑक्शन प्रक्रिया के ज़रिये कमाई में तब्दील हो रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर निगरानी और फील्ड से स्क्रैप की पहचान व रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाए जाने का असर साफ दिखा है। आंकड़े बताते हैं कि जहां पिछले वित्तीय वर्षों में ऑक्शन की संख्या सीमित रही, वहीं चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी तक 221 नीलामियां पूरी हो चुकी हैं। विशेष रूप से 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की पहचान कर 34 वाहनों को सफलतापूर्वक नीलाम किया गया, जो लंबे समय से टैक्स और दस्तावेजी उलझनों के कारण खड़े-खड़े जंग खा रहे थे। राजस्व के मामले में अलवर वृत्त 24.79 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे रहा, जबकि जयपुर जिला वृत्त ने करीब 22 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके अलावा दौसा, भरतपुर, कोटा और जयपुर शहर वृत्तों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया।

सीएम है तो मुमकिन है : दो घंटे, एक फोन कॉल और सिस्टम दौड़ा सरपट



24 न्यूज अपडेट

जयपुर। सुशासन अगर फाइलों से निकलकर ज़मीन पर उतरता है, तो उसकी पहचान समय से होती है—और शुक्रवार को वही तस्वीर साफ दिखाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज एक परिवेदना पर खुद संज्ञान लिया, परिवादी से सीधा संवाद किया और डूंगरपुर जिला प्रशासन ने महज़ दो घंटे में समाधान देकर यह जता दिया कि इच्छाशक्ति हो तो व्यवस्था दौड़ती है। मामला डूंगरपुर जिले के साबला तहसील स्थित बोडीगाम छोटा गांव का था। यहां के निवासी जितेंद्र सिंह ने अपने बच्चों—संयम और क्रिया—के मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। सात दिन बीतने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा तो उन्होंने संपर्क पोर्टल का दरवाज़ा खटखटाया। बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची—और वहीं से काम ने रफ्तार पकड़ ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवादी से फोन पर बातचीत कर स्थिति जानी। उसी क्षण मुख्यमंत्री कार्यालय से डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और कागज़ों की धीमी चाल को पीछे छोड़ते हुए दो घंटे के भीतर दोनों प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मिलने के बाद प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। परिवादी जितेंद्र सिंह ने राहत मिलने पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया।

शिल्पग्राम में 'गोल्डन बाजार' का मंचन कल



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित मासिक नाट्य संध्या 'रंगशाला' के अंतर्गत रविवार 1 फरवरी को 'गोल्डन बाजार' नाटक का मंचन किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक फ़ुरकान खान ने बताया की प्रति माह आयोजित होने वाली मासिक नाट्य संध्या रंगशाला के अंतर्गत पोटली थिएटर ग्रुप मुंबई द्वारा गोल्डन बाजार नाटक का मंचन रविवार 1 फरवरी को सायं 7 बजे शिल्पग्राम उदयपुर स्थित दर्पण सभागार में किया जाएगा। इस मनोरंजक नाटक के लेखक पवन उत्तम एवं विजय सिंह परमार है। इस नाटक की स्टोरी एवं डिजाईन विजय सिंह परमार तथा संकल्पना अंशु श्रीवास्तव ने की। इस कार्यक्रम में आमजन का प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com

हनुमानगढ़–गोगामेड़ी रेल खंड : 80 से 110 किमी प्रतिघंटा, सफर होगा तेज़ और भरोसेमंद



24 न्यूज अपडेट

हनुमानगढ़। रेल यात्रियों के लिए राहत और क्षेत्र के लिए विकास का संकेत देते हुए हनुमानगढ़–गोगामेड़ी रेल खंड ने गति की नई दहलीज़ पार कर ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले इस करीब 100 किलोमीटर लंबे एकल लाइन खंड पर ट्रेनों की अधिकतम सेक्शनल स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दी है। यह फैसला न केवल यात्रा समय घटाएगा, बल्कि रेल संचालन को अधिक सुगम और आधुनिक भी बनाएगा। यह उपलब्धि किसी एक कदम का नतीजा नहीं, बल्कि महीनों की तकनीकी मेहनत और ढांचागत सुधारों का परिणाम है। सिग्नलिंग प्रणाली के व्यापक उन्नयन, विद्युतीकरण, ट्रैक स्ट्रेंथनिंग और संरचनात्मक सुधारों के बाद इस खंड को तेज रफ्तार के लिए उपयुक्त घोषित किया गया। नई सिग्नलिंग व्यवस्था ने ट्रेन परिचालन को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया है, वहीं लंबे समय से लागू कई गति प्रतिबंध अब इतिहास बन गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, इन सुधारों का सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। ट्रेनों का यात्रा समय घटेगा, संचालन में लचीलापन आएगा और संरक्षा मानकों को और मजबूती मिलेगी। साथ ही, इस खंड पर भविष्य में अधिक ट्रेनों के संचालन का रास्ता भी खुलेगा, जिससे यात्री सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा।

विक्रम भट्ट दंपती को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत नामंजूर



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि सिनेमा की चकाचौंध के पीछे छिपी कथित आर्थिक धोखाधड़ी को इस स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। करोड़ों रुपये की ठगी के चर्चित मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और सह-आरोपी मेहबूब अंसारी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जस्टिस विनोद कुमार भारवनी की पीठ ने जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए माना कि जांच की मौजूदा अवस्था में बेल देना न्यायोचित नहीं होगा। अदालत के समक्ष राज्य की ओर से रखे गए तर्कों ने यह तस्वीर उभारी कि मामला केवल कारोबारी असहमति का नहीं, बल्कि सुनियोजित आर्थिक अपराध का है। अभियोजन ने बताया कि जांच अभी निर्णायक मोड़ पर है, महत्वपूर्ण पूछताछ शेष है और गवाहों पर दबाव बनाने की आशंका भी सामने आई है। ऐसे में आरोपियों को रिहा करना जांच की दिशा को प्रभावित कर सकता है। फर्जी बिल, अलग-अलग नाम और पैसों की घुमावदार राह जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अलग-अलग नामों से फर्जी बिल तैयार कर शिकायतकर्ता से रकम ट्रांसफर करवाई। यह राशि विभिन्न खातों में पहुंचाई गई और फिर अपने ही खातों में डालकर निजी देनदारियां चुकाने में उपयोग की गई। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 4.23 करोड़ रुपये से अधिक की रकम अलग-अलग खातों में मंगवाई गई, जिसमें से करीब 1.65 करोड़ रुपये सीधे आरोपियों के खातों में समाहित पाए गए। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि सह-आरोपी मेहबूब अंसारी की भूमिका केवल नाममात्र नहीं, बल्कि सक्रिय और प्रभावी रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, यदि इस चरण में जमानत दी गई तो साक्ष्यों और गवाहों पर असर पड़ने का वास्तविक खतरा है।

30 करोड़ की कहानी, चार फिल्मों का सपना

मामले की जड़ें उदयपुर में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ी हैं, जिसमें इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और इंदिरा आईवीएफ के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने फिल्म उद्योग से जुड़े आठ लोगों पर 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार इवेंट के जरिए संपर्क बना और बायोपिक के प्रस्ताव से बात आगे बढ़ी। मुंबई के स्टूडियो में हुई मुलाकातों के बाद चार फिल्मों का पैकेज सामने रखा गया—47 करोड़ की लागत, 100 से 200 करोड़ तक मुनाफे का वादा। आरोप है कि इस भरोसे के आधार पर विभिन्न कर्मचारियों और सहयोगियों के खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई। अलग-अलग चरणों में करीब 2.45 करोड़ रुपये और एक एंटरटेनमेंट कंपनी के जरिए 42.70 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।

दो फिल्में रिलीज, दो अधूरी—और सवाल अधूरे नहीं हकीकत यह रही कि चार में से केवल दो फिल्में रिलीज हो सकीं। तीसरी फिल्म आंशिक रूप से बनी और चौथी पर काम शुरू तक नहीं हुआ। शिकायत में आरोप है कि चौथी फिल्म के नाम पर करीब 25 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया। यही वह बिंदु है जहां सपनों की पटकथा, अदालत की फाइलों में धोखाधड़ी के कथानक में बदल गई।

जो शांत है वह संत है, जो अशांत है वह खत्म है - आचार्य पुलक सागर



24 न्यूज अपडेट

सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। नगर के ऋषभ वाटिका में आचार्य पुलक सागर महाराज ने कहा—जो शांत है वह संत है, जो अशांत है वह खत्म है। ज्यादा अकड़कर मत जियो, झुककर जीना प्रारंभ करो। जो झुकता है वही जीवन में ऊपर उठता है, ज्यादा अकड़ोगे तो जड़ से काटे जाओगे। हाथों की दस उंगलियों का उदाहरण देते हुए कहा कि हथेली की अंतिम उंगली सबसे छोटी होती है, लेकिन जब परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर दर्शन करते हैं तो वही उंगली भगवान के सामने होती है। जिसका नेचर अच्छा है उसका फ्यूचर अच्छा होता है। आदमी को बदलने के लिए व्यवहार बदलने की जरूरत है, बड़ा बनने के लिए सर्वस्व समर्पित करना पड़ता है। परिवार में सभी सदस्य अहंकार का त्याग करेंगे तो परिवार में शांति कायम होगी। सभा के पूर्व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया, वहीं आचार्य पुलक सागरजी का पाद प्रक्षालन कीर्ति भाई शाह परिवार द्वारा किया गया। सीमा जैन व पिंकी जैन बांसवाड़ा द्वारा जिनवाणी भेंट की गई।

भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में वेस्ट ज़ोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आग़ाज़ 3 से

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। खेल और उच्च शिक्षा के संगम का सशक्त मंच बनने जा रहा है भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, जहां वेस्ट ज़ोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टूर्नामेंट (पुरुष वर्ग) 2025–26 का उद्घाटन समारोह मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को प्रातः 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन विश्वविद्यालय के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स ग्राउंड में होगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ से संबद्ध इस राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में पश्चिमी भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमें सहभागिता करेंगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री गौरव श्रीवास्तव, आईपीएस मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की चेयरपर्सन कर्नल (मानद) प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत करेंगी। समारोह में विद्या प्रचारिणी सभा के सचिव डॉ. महेन्द्र सिंह राठौड़, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. चेतन सिंह चौहान, विश्वविद्यालय खेल मंडल के अध्यक्ष डॉ. अभिमन्यु सिंह राठौड़, भूपाल नोबल्स संस्थान के प्रबंध निदेशक श्री मोहब्बत सिंह राठौड़, कुलसचिव डॉ. निरंजन नारायण सिंह राठौड़ सहित अनेक शिक्षाविद् और खेल प्रशासक उपस्थित रहेंगे। टूर्नामेंट के आयोजन सचिव डॉ. हितेश चन्द्र रावल ने बताया कि यह प्रतियोगिता न केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी, बल्कि विश्वविद्यालयों के बीच खेल भावना, अनुशासन और नेतृत्व कौशल को भी सुदृढ़ करेगी। भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, जो वर्ष 2016 में स्थापित हुआ और जिसकी शैक्षणिक परंपरा विद्या प्रचारिणी सभा (स्थापना 1923) से जुड़ी है, लगातार खेल और शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित विकास का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह आयोजन उसी परंपरा की अगली कड़ी माना जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का मानना है कि ऐसे अंतर-विश्वविद्यालयीय टूर्नामेंट विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं।

विश्वकर्मा जयंती पर हर्षोल्लास के साथ नगर में निकली शोभायात्रा



24 न्यूज अपडेट

सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। विश्वकर्मा जयंती पर शनिवार को गुजराती मेवाड़ा सुथार समाज सागवाड़ा द्वारा हर्षोल्लास के साथ नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। विश्वकर्मा जयंती पर गुजराती मेवाड़ा सुथार समाज द्वारा शनिवार प्रातः नगर के विश्वकर्मा मंदिर से बैंड-बाजों व भजन-कीर्तन के साथ भगवान की श्रृंगारित अष्टधातु की प्रतिमा गंगाघुटी पर सवार शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा मंदिर परिसर से मांडवी चौक, कंसारा चौक, जूना मंदिर, सुथारवाड़ा, सलाटवाड़ा सहित विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची, जहां भगवान विश्वकर्मा की महाआरती एवं केसर चढ़ाई का लाभ यजमान परिवार द्वारा लिया गया। नर्मदाशंकर, धनेश्वर, लालशंकर और भूपेश सुथार ने आरती व केसर चढ़ाया और वर-घोड़े की बोली का लाभ लिया। दोपहर में समाज के नोहरा भवन में महाप्रसाद तथा सायंकाल मंदिर में द्वितीय महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष धर्मेंद्र सुथार, उपाध्यक्ष जितेंद्र, रविंद्र सुथार, रूपेश सुथार, कन्हैयालाल, अरविंद, हरिश सुथार, निखिल सुथार, रोहित, प्रकाश, राजेंद्र सुथार, देवशंकर सुथार, ओमप्रकाश सुथार, दयालाल, भारतानंद, अशोक, जितेंद्र, रूपेश, लालशंकर, रोहित, हेमंत सुथार, अजय, हिमांशु, कवित, चारु, प्रफुल, राजेंद्र सहित समस्त पंच व महिला-पुरुष उपस्थित रहे।

गणेशपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मिली शैक्षणिक सामग्री



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भींडर पंचायत समिति के अंतर्गत बड़गांव पंचायत के गणेशपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय पहल देखने को मिली। खेरोदा निवासी भामाशाह मदनलाल बोकड़िया की ओर से विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। 31 जनवरी को आयोजित इस वितरण कार्यक्रम में बच्चों को नोटबुक (हिंदी, अंग्रेज़ी एवं गणित), पेंसिल तथा प्रेप स्कूल किट प्रदान की गई, जिसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर और स्केल शामिल थे। सामग्री प्राप्त करते ही बच्चों के चेहरों पर उत्साह और पढ़ाई के प्रति नया आत्मविश्वास साफ झलकता नजर आया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हंसराज साहू, अध्यापक राकेश कुमार मीणा एवं सियाराम मीणा उपस्थित रहे। शिक्षकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार का सहयोग विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें नियमित अध्ययन के लिए भी प्रेरित करता है। विद्यालय परिवार की ओर से भामाशाह मदनलाल बोकड़िया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सहभागिता का अनुकरणीय उदाहरण बताया गया। साथ ही विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए यह आशा भी जताई गई कि भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा।

उदयपुर में माहेश्वरी समाज की उद्यमी ताकत एक मंच पर, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक सहयोग का संकल्प



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 31 जनवरी। उद्योग, उद्यमिता और सामाजिक सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से माहेश्वरी इंटरनेशनल बिज़नेस फाउंडेशन (एमआईबीएफ) की ओर से उदयपुर में आयोजित बिज़नेस नेटवर्किंग मीट माहेश्वरी समाज की उद्यमी शक्ति के सशक्त प्रदर्शन के रूप में सामने आई। इस अवसर पर समाज के 100 से अधिक उद्यमियों, प्रोफेशनल्स और उद्योगपतियों ने सहभागिता कर आपसी सहयोग और नैतिक व्यापारिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। शुरुआत डॉ. नम्रता माहेश्वरी के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि समाज आधारित संगठित बिज़नेस नेटवर्क न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनते हैं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और दीर्घकालिक सहयोग की मजबूत नींव भी रखते हैं। एमआईबीएफ के संस्थापक संतोष लाहोटी एवं प्रशांत माहेश्वरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में एक संगठित, गुणवत्ता-आधारित और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बिज़नेस नेटवर्क समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने भरोसेमंद संपर्कों और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज के व्यवसायों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने एमआईबीएफ को समाज के लिए दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि यह मंच उद्यमियों को आपस में जोड़कर रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने समाज के अधिक से अधिक उद्यमियों से इस पहल से जुड़ने का आग्रह किया। प्रख्यात उद्योगपति विनय राठी ने कहा कि संपर्क, सहयोग और नैतिकता के आधार पर छोटे व मध्यम उद्योग भी तेजी से विकास कर सकते हैं। वहीं, विशिष्ट अतिथि भींडर एसडीएम रमेश बहेड़िया एवं प्रमोद छापरवाल ने एमआईबीएफ के प्रयासों को समयानुकूल और प्रभावी बताते हुए इसकी सराहना की। कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वरूप देते हुए कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद से आए एमआईबीएफ के प्रमुख सदस्य विमल परवाल, दिनेश भट्टड़ एवं मुकेश चेचानी ने भी सहभागिता की। बैठक में एस. एन. माहेश्वरी एवं अक्षय काबरा की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। आयोजन की सफलता में हितेश भदादा, भरत बाहेती, मयंक मूंदड़ा, श्याम मोहता, तरुण असावा एवं पंकज तोषनीवाल के योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित उद्यमियों ने अपना परिचय देते हुए व्यवसायिक संवाद और नेटवर्किंग को मजबूत किया। कार्यक्रम का समापन श्रद्धा गट्टानी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह आयोजन माहेश्वरी समाज की संगठित उद्यमी शक्ति और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की मजबूत नींव के रूप में याद किया गया।

राष्ट्रीय हैंडबॉल में राजस्थान ने जीता सिल्वर, चित्तौड़गढ़ के पांच खिलाड़ी चमके



24 न्यूज अपडेट

चित्तौड़गढ़। 69वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता (अंडर-19 वर्ग) में राजस्थान की टीम ने अपनी दमदार खेल भावना और अनुशासन का परिचय देते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस शानदार उपलब्धि में चित्तौड़गढ़ जिले के पांच खिलाड़ियों का विशेष योगदान रहा, जो राज्य का मान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते रहे। राजस्थान की उपविजेता टीम में शामिल ये पांच खिलाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुरोहितों के सांवता के छात्र हैं। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक जवान सिंह चुंडावत ने बताया कि प्रतियोगिता गुजरात के सोमनाथ में 27 से 31 जनवरी तक आयोजित की गई थी। फाइनल मुकाबले में राजस्थान और गुजरात के बीच रोमांचक खेल देखने को मिला। 4 गोल के अंतर से राजस्थान को हार मिली, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। सेमीफाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 25-14 से करारी शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। राजस्थान की ओर से पुरोहितों के सांवता के खिलाड़ी— अंकित अहीर, कमलेश सुथार, दीपक अहीर, कमलेश अहीर और गोपाल अहीर ने टीम भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल कौशल का लोहा मनवाया। कोच दलिप चौधरी, टीम मैनेजर भगवान भादू, सहायक कोच शिवराज श्रृंगी और दलाधिपति राजेश कुमार ओझा के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने राज्य का नाम गर्व से रोशन किया। खेल उत्साह बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता स्थल पर रतन अहीर, द्वारकाप्रसाद गदिया, जगदीश समदानी और बद्री जाट भी मौजूद रहे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर चित्तौड़गढ़ का नामः शारीरिक शिक्षक जवान सिंह चुंडावत ने यह भी बताया कि इसी विद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रितेश अहीर का चयन आगामी अप्रैल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स हैंडबॉल प्रतियोगिता (अंडर-17) के लिए हुआ है। रितेश का चयन कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान हुआ था और अब वे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना कौशल दिखाएंगे।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।